पुलिस के एजेंडा में चोर पकड़ना ही न हो तो वह कैसे पकड़ा जा सकता है

तमाम सुबूत दिए जाने के बावजूद भी एक माह में पुलिस के हाथ खाली

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) गतांक में अपराधी पड़ रहे भारी, पुलिस की ज्ञात अपराधियों से यारी शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि सेक्टर सात की मार्केट में दिनांक 13 मई की शाम आठ बजे एडवोकेट शिव कुमार जोशी की जेब से उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। करीब एक माह बीत जाने के बावजूद अभी तक न कोई गिरफ्तारी न कोई बरामदगी।

सीपी विकास अरोड़ा : धन्य है फरीदाबाद की 'कर्मठ' एवं 'ईमानदार' पुलिस

गिरफ्तारी एवं बरामदगी हो भी कैसे सकती है जब पुलिस ने ठान ही रखा हो कि काम नहीं करना। जी हां, इस मामले में पुलिस का व्यवहार ऐसा ही कुछ साबित करता है। एडवोकेट जोशी जब पुलिस चौकी गए थे तो वहां मौजूद एएसआई वेदराम ने कहा कि वह गुमशुदगी की रपट लिख सकता है चोरी का केस दर्ज नहीं करेगा। जोशी के बहुत जोर देने पर वेदराम ने उन्हें समझाया कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे चोर को पकड़ने का और चोरी का मुकदमा दर्ज करने के बाद वे केस को अनट्रेस भी दिखा सकते हैं। क्या कमाल का तर्क है, यानी बिना केस दर्ज किए तो वह चोर को पकड़ने की बात करते हैं और मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद वह अनट्रेस होने का विकल्प बताते हैं। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद रात दो बजे एफआईआर नंबर ३७२ दर्ज कर ली गई।

चोरों के इस गिरोह के लिए इतना समय काफी लाभकारी सिद्ध हुआ। पुलिस की इस काहिली एवं हरामखोरी का पूरा लाभ उठाते हुए चोर गिरोह ने जोशी के तीन बैंक खातों से 1,36,520 रुपये साफ कर दिए जिसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई द्वारा बचाया जा सकता था।

अगली सुबह जब जोशी को अपने अकाउंटों में हुई सेंधमारी की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया; लेकिन पुलिस इसके प्रति पूरी तरह से उदासीन बनी रही। उधर जोशी ने अपनी सक्रियता एवं सूझबूझ से उस जगह का पता लगा लिया जहां से चोर ने चोरी के पैसे से पहली खरीदारी की थी और वहीं से चोर का फोटो भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने पता लगा लिया कि चोर गिरोह के दो खाते दिल्ली में हैं जहां पूरा पैसा ट्रांसफर हुआ था। एक खाता नंबर 918020110872063 यूटीआई बैंक, आरपीके जीएसटी सुविधा केंद्र के नाम से है। जो कि एस 415 मेन रोड, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, नियर मदर डेयरी नई दिल्ली पर स्थित है। इसका लैंड लाइन नंबर 01135725691 और मोबाइल नंबर 9968398314 है।

जोशी ने जब इस नंबर पर बात की तो उसने स्वीकार किया कि हां उसके खाते में 83,700 की राशि आई है जो उसने कमीशन काट कर रकम मंगाने वाले को सौंप दी है। दूसरा खाता नंबर 9744201000007 पेटीएम बैंक नोएडा ब्रांच में 30,600 की रकम पहुंची। खाता धारी का नाम मो. जाहिद शॉप नंबर सी 116, मेन मार्केट समोसा चौक, नई दिल्ली है।

इतनी तफ्तीश तो खुद जोशी जी ने ही कर ली जबकि निठल्ली पुलिस कुछ न कर सकी। हां, जोशी द्वारा यह सारी कहानी बताने के बाद पुलिस वाले जरूर उक्त पतों पर 'मुलाकात' करने पहुंच गए और खाली एक नोटिस देकर चले आए, बदले में क्या लेकर आए ये तो वही जानें। पूछताछ करने पर पुलिस चौकी वालों ने जोशी को बताया कि यह साइबर क्राइम का बड़ा टेक्निकल मामला है जो उनकी समझ से बाहर है। इसलिए बेहतर होगा कि जोशी जी जाकर उच्चाधिकारियों से मिलें और केस को अन्यत्र ट्रांसफर करवा लें।

सीपी साहब ने वेदराम जैसा नायाब हीरा सेक्टर सात की चौकी में छिपा कर क्यों रखा है ? इसे तो पूरी जिला पुलिस को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा जाना चाहिए। बेशक हर चौकी थाने में एफआईआर लिखे जाने के वक्त ऐसे ही ड्रामे होते हैं लेकिन वेदराम ने, शिकायतकर्ता को समझाने के लिए जो दलील दी है उसका कोई मुकाबला नहीं।

प्लास्टिक बैनर-प्लेकार्ड से दिया प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ का नारा

सीएमओ कार्यालय में ऐसे मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस

फ़रीदाबाद (फ़रीदाबाद) काम नहीं केवल नारों में विश्वास रखने वाली खट्टर सरकार के अधिकारी भी इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ थीम के प्रति जागरूक करने के लिए प्लास्टिक के बैनर-प्लेकार्ड का इस्तेमाल कर अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली।

स्मार्ट सिटी होने के कारण फरीदाबाद में प्लास्टिक, पॉलिथीन से बनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है। पांच जून को सभी विभागों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सीएमओ कार्यालय में भी इस दिवस की खानापूर्ति की गई। कार्यालय परिसर में दो जगह प्लास्टिक के बैनर लगाए गए जिनमें संदेश छपा था विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। यही नहीं इस मौके पर कर्मचारी प्लास्टिक से बनी तख्तियां भी लिए थे, जिन पर पर्यावरण संरक्षण संबंधित नारे छपे हुए थे। इस दौरान अधिकारियों ने दो पौधे रोप कर पर्यावरण संरक्षण की रस्म अदा की।

अवैध यूनिटों से होती है काली कमाई इसलिए नहीं होती कार्रवाई

सरूरपुर में अवैध इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण नियंत्रण, नगर निगम, डीटीपी शिकायत मिलने पर भी नहीं करते कार्रवाई

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सरूरपुर में अवैध इंडस्ट्री चाहे प्रदूषण फैलाएं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा एवं निर्माण करें, ग्रीन बेल्ट बर्बाद करें या अतिक्रमण करें प्रशासन कार्रवाई करना तो दूर शिकायत मिलने पर भी उधर झांकता तक नहीं। अवैध इंडस्ट्रियल यूनिटों से सरकार को भले ही कोई लाभ न हो लेकिन अधिकारियों के वारे न्यारे हैं यही कारण है कि यहां अराजकता व्याप्त है। अधिकारियों को जेब में रखने वाले अवैध कारोबारी बेखौफ होकर वायु और जल प्रदूषण फैला रहे हैं।

सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सौ किलोमीटर दूर से पराली का तथाकथित धुआं तो दिख जाता है लेकिन सरूरपुर में धड़ल्ले से जलाए जा रहे ई वेस्ट से उठने वाला काला धुआं उनको नजर नहीं आता। सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में धातु गलाने की करीब दो सौ अवैध फैक्टरियां कार्यरत हैं। इन फैक्टरियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए यहां ई वेस्ट जलाकर उनसे धातु निकालने का अवैध धंधा जोरों पर चल रहा है। ई वेस्ट में कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा जैसी धातुओं के अलावा प्लास्टिक, लीथियम, क्रोमियम जैसे खतरनाक रसायनिक यौगिक होते हैं। इसको जलाने से वातावरण में कैंसर कारक बिस-फिनोल, दम घोंटू और ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिम्मेदार कार्बन डाई ऑक्साइड, खतरनाक कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर आदि रसायन हवा में घुल कर उसे जहरीला बनाते हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता वरुण श्योकंद बताते हैं कि फरीदाबाद देश के सर्वाधिक प्रदूषित

शहरों में शामिल है जहां अवैध डाइंग यूनिट और सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ई कचरे को बड़े पैमाने पर जलाए जाने से यहां का पानी और हवा दोनों ही गंभीर स्तर तक दूषित हो चुके हैं। उनका आरोप है कि फरीदाबाद के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जानबूझ कर इस सब की अनदेखी करते हैं क्योंकि ई वेस्ट जलाने वाले सुविधा शुल्क चुकाते हैं। शिकायत मिलने पर सुविधा शुल्क के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, यही वजह है कि शिकायतें होते रहने के बावजूद यह धंधा बढ़ता ही जा रहा है। हां, नौकरी सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई के नाम पर नोटिस थमा दी जाती है, मामला ठंडा पड़ने पर फाइल भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है।

बोर्ड से अभयदान पाए कारोबारी भी उस जगह को छोड़ कर पास ही किसी दूसरी जगह ई कचरा जलाने लगता है। हालात यह हैं कि पूरे शहर में कूड़ा-कबाड़ जलाया जा रहा है लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। संदर्भवश बताते चलें कि शहर के बीच स्थित नीलम फ्लाईओवर के नीचे इसी तरह कबाड़ जलाने का काम होता था और इसी आग जलाने के कारण पुल भी टूट गया था। यहां शासन प्रशासन को कबाड़ा जलाया जाना नजर नहीं आता था।

वरुण श्योकंद ने कबाड़ जलाए जाने के खिलाफ 2022 में एनजीटी में शिकायत की थी। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था। एनजीटी के पहले से भी निर्देश हैं, बावजूद इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हीलाहवाली वाला रवैया अपनाए हुए हैं।

मालूम हो कि सरूरपुर में चल रही अवैध इंडस्ट्री में से अनेक तो सरकारी जमीन पर कब्जा हैं। बाकी में से अधिकतर का न तो नक्शा पास है, न ही नगर निगम में उनका कोई रिकॉर्ड है और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिली है। बावजूद इसके उन पर हूडा, नगर निगम और या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई नहीं करते। जब दबाव आता है तो झूठ मूठ का तोड़फोड़ या निरीक्षण अभियान चलाया जाता है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।

जाहिर है कि सरूरपुर में होने वाली मोटी कमाई का हिस्सा इन अधिकारियों को भी मिलता है इसीलिए दिखावटी कार्रवाइयों के बीच धंधा चलता रहना है, भले ही इससे पर्यावरण बर्बाद हो या आम आदमी का नुकसान हो।

कितना ही झूठ बोलो ये पब्लिक है सब जानती है

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) खुद को कानून से ऊपर समझने वाले केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गूजर ने विकास तीर्थ यात्रा के नाम पर हाईवे पर स्टंट यात्रा करते हुए जनता को अपनी और भाजपा सरकारों की उपलब्धियां गिनवाने के नाम पर अपनी ताकत का भौंडा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा कि बीते नौ साल में मोदी के नेतृत्व में और आठ साल में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में फरीदाबाद का स्वरूप बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरह वह भी सफलता का सेहरा अपने नाम करते हुए ढिंढोरा पीटते और जनता की समस्याओं, शहर के बिगड़े और भ्रष्ट निजाम, आधारभूत सुविधाओं के टोटे पर पर्दा डालते नजर आए। मंत्री जी जनता आपकी नहीं अपनी निगाहों से देखती है, उसकी नजरों से फरीदाबाद कुछ ऐसा दिखता है।

मंत्रीजी करीब नौ साल पहले आपने मंझावली पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया था। जनता देख रही है कि नौ साल में भी यह पुल बन कर तैयार नहीं हुआ। इस दौरान पुल की लागत भी दो गुनी हो गई। यदि यह सही वक्त पर बन कर तैयार होता तो फरीदाबाद से नोएडा जाने वाले पर अब तक अरबों रुपये का ईंधन बच चुका होता, दूरी कम होने के कारण लाखों मानव घंटों की बचत भी हुई होती। जनता को होने वाले इस नुकसान की भरपाई आपकी लेटलतीफ सरकार करेगी क्या ?

स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले मंत्री जी जनता आपके मेवला महाराजपुर के नए नवेले अर्बन हेल्थ सेंटर को देख रही है जिसमें न स्टाफ न उपकरण-दवाइयां। जनता छांयसा मेडिकल कॉलेज की हालत भी देख रही है और बीके अस्पताल की भी, जहां कभी दवाओं का टोटा होता है

सड़कों पर सर्कस करना इनसे सीखे शहर की जनता

तो कभी एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं रहतीं, स्टाफ की कमी के कारण अधिकतर मरीजों को दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की सच्चाई भी जनता देख रही है। सरकारी अस्पतालों में तो खैर स्तरीय चिकित्सा सेवाएं मिलती नहीं हैं, भुगतान नहीं होने के कारण अधिकतर निजी अस्पताल वालों ने आयुष्मान मरीजों का इलाज करना ही छोड़ दिया है।

कॉरपोरेट स्कूल डीपीएस खुलवा कर शिक्षा क्षेत्र में उन्नति का दावा करने वाले मंत्री जी जनता आपके गोद लिए गांव के प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को मिल रही 'सुविधाओं' को भी देख रही है।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर समर्थकों को खतरनाक तरह से कार पर लटकाकर हुड़दंगियों की तरह स्टंट करते वक्त आपको जनता के रोजाना इस्तेमाल में आने वाली शहर की सड़कों का ख्याल आना चाहिए था। एक-दो चौक से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज होते हुए चिमनी बाई चौक को जाने वाली सड़क के गहरे गड्ढों को आप भी मोदी की तरह नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। यही नहीं शहर की अनेक टूटी सड़कें और उफनते सीवर आपके विकास का नमूना हैं।

सत्तारूढ़ होने के बाद से बीते नौ साल में निजी संपत्ति में अकूत विकास करने वाले मंत्री जी जनता शहर के विनाश को भी देख रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर चार हजार करोड़ रुपये कैसे डकारे गए जनता ने देखा। अब बड़खल झील भरे जाने की अवैज्ञानिक परियोजना पर पानी की तरह बहाए जा रहे धन को भी गर्मी में पानी को तरसने और पानी खरीद कर पीने को मजबूर होने वाली जनता देख रही है।

चार बूंद पानी बरसते ही पूरा सारा शहर कीचड़ से भर जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। यदि इसी का नाम विकास है तो यहां की जनता पहले भी देख रही थी और अब भी देख रही है। नगर निगम के घोटाले, 'हूडा' की लूट, पुलिस की मार सभी तो आपके विकास एवं सुशासन की कहानियां कह रहे हैं।